

No. CD-11012/01/2020-Coord.
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Coordination Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 10th November, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of October, 2021.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of October, 2021 is enclosed herewith for information.



(Prashant Kumar)
Section Officer(Coord)

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary, Rashtrapati Bhavan New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB, Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of October, 2021.

1. **Award and construction of National Highways:** The Ministry has constructed 4,450 K.M. of National Highways up to October in 2021-22 as compared to 4,956 K.M. up to October in 2020-21. The award figure is 4,913 K.M. during this period as compared to 5,777 K.M. in the previous year.
2. **Safety measures for children below four years of age, riding or being carried on a motor cycle:** Ministry vide draft notification, GSR 758 (E) dated 21st October 2021, has proposed to amend rule 138 of CMVR, 1989 and has prescribed norms related to safety measures for children below four years of age, riding or being carried on a motor cycle. This draft notification specifies use of a safety harness & crash helmet and restricts speed of such motor cycles to 40 kmph.
3. **Extension of relief measures for contractors/Developers:** This Ministry has granted extension of relaxation in schedule H/G related to EPC/HAM Projects, till 31.12.2021 to improve the liquidity of funds available with the contractors and concessionaire; and also arrangement regarding payment to approved sub-contractor through Escrow Account will be continued till 31.12.2021 or the completion of the work by the sub-contractor, whichever is earlier.
4. **Scheme for grant of Award to the Good Samaritan:** This Ministry has issued Guidelines for the "Scheme for grant of Award to the Good Samaritan who has saved life of a victim of a fatal accident involving a motor vehicle by administering immediate assistance and rushing to Hospital/Trauma Care Centre within Golden Hour of the accident to provide medical treatment". The Scheme mainly aims to motivate the general public to help the road accident victims in emergency situation, inspire and motivate others to save innocent lives on road. The amount of award for the Good Samaritan(s) would be 5,000/- per incident. MoRTH will provide Rs. 5 Lakhs as initial grant to the Transport Department of the State/UT for making payment to the Good Samaritans. The Scheme is effective w.e.f 15th October, 2021.
5. **Mass Emission Standards for E12 and E15 Fuels:** Ministry of Road Transport and Highways notified mass emission standards for E 12 (12% ethanol with Gasoline) and E 15 (15% Ethanol with Gasoline) fuels. This will enable the Automotive Industry to manufacture E12 and E 15 complaint motor vehicles.
6. **Gati Shakti-National Master Plan for Multi Modal Connectivity:** Hon'ble Prime Minister on 13.10.2021 inaugurated the ambitious "PM Gati Shakti-National Master Plan (NMP)" for multi modal connectivity. The Hon'ble Prime Minister highlighted the need for holistic and integrated development across departments to create next generation infrastructure by fostering 'will for progress, work for

progress, wealth for progress, plan for progress and preference for progress. It was emphasized that structured and well-coordinated engagement process is required to address needs of stakeholders and to avoid missing out key stakeholders on the ground, a careful mapping needs to be conducted for every project going forward.

7. **Special Campaign regarding Disposal of Pending Matters:** In view of Cabinet Secretariat's instructions for disposal of pending matters in the month of October, this Ministry disposed of 802 numbers of MP References, 125 State Govt. References, 1333 Public Grievances and 621 PG Appeals during special campaign . Besides, 50,500 files of MORTH and its attached offices including NHAI/NHIDCL have been reviewed and more than 25,000 files have been weeded out as per Record Retention Schedule during the period. The Ministry and its attached, subordinate and autonomous organizations have undertaken mass Cleanliness Drive in office premises as a part of campaign.
8. **Standing Finance Committee (SFC) meetings:** In the month of October, 2021, a total 13 nos. of projects were considered by the Standing Finance Committee. The 13 projects of length 301.084 Km and total capital cost of Rs. 6,282.82 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषय: मंत्रिमंडल के लिए अक्टूबर, 2021 माह का मासिक सारांश।

1. राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण : मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में अक्टूबर तक 4,956 किलोमीटर की तुलना में वर्ष 2021-2022 में अक्टूबर तक 4,450 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। इस अवधि के दौरान सौंपा गया आंकड़ा 4913 किलोमीटर है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 5,777 किमी था।
2. चार साल से कम उम्र के बच्चों के मोटर साइकिल पर सवारी या ले जाने के लिए सुरक्षा उपाय: मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना, सा.का.नि 758 (अ) दिनांक 21 अक्टूबर 2021 के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों के मोटर साइकिल पर सवारी या ले जाने के लिए सुरक्षा उपाय मानदंड निर्धारित किए हैं। यह मसौदा अधिसूचना एक सुरक्षा कवच और क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करती है और ऐसे मोटर साइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करती है।
3. ठेकेदारों/विकासकों के लिए राहत उपायों का विस्तार: इस मंत्रालय ने ठेकेदारों और रियायतग्राही के पास उपलब्ध धन की तरलता में सुधार के लिए ईपीसी/एचएएम परियोजनाओं से संबंधित अनुसूची एच/जी में छूट को 31.12.2021 तक बढ़ा दिया है; और स्वीकृत उप-ठेकेदार को एस्करो खाते के माध्यम से भुगतान के संबंध में भी व्यवस्था 31.12.2021 तक या उप-ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी।
4. नेक व्यक्ति को पुरस्कार देने की योजना: इस मंत्रालय ने "नेक व्यक्ति को पुरस्कार देने की योजना" के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने एक मोटर वाहन से जुड़ी एक घातक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर तत्काल सहायता करके उस व्यक्ति को अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर में चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए पहुँचाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करना, दूसरों को सड़क पर निर्दोष जीवन बचाने के लिए प्रेरित और अभिप्रेरित करना है। नेक व्यक्तियों को प्रति घटना के लिए 5,000/- रुपये पुरस्कार की राशि प्रदान की जायेगी। एमओआरटीएच राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन विभाग को नेक व्यक्ति को भुगतान करने के लिए प्रारंभिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपये देगा। यह योजना 15 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है।
5. ई12 और ई15 ईंधन के लिए मास उत्सर्जन मानक: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई 12 (गैसोलीन के साथ 12 प्रतिशत इथेनॉल) और ई 15 (गैसोलीन के साथ 15% इथेनॉल) ईंधन के लिए मास उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है। इससे ऑटोमोटिव उद्योग ई12 और ई15 का अनुपालन करने वाले मोटर वाहनों का निर्माण कर सकेगा।
6. गति शक्ति- मल्टी मॉडल संपर्कता के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान -: माननीय प्रधान मंत्री ने 13.10.2021 को मल्टी मोडल संपर्कता के लिए महत्वाकांक्षी "पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी)" का उद्घाटन

किया। माननीय प्रधान मंत्री ने 'प्रगति के लिए इच्छा, प्रगति के लिए काम, प्रगति के लिए धन, प्रगति के लिए योजना और प्रगति के लिए वरीयता' को बढ़ावा देकर अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए विभागों में समग्र और एकीकृत विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस बात पर जोर दिया गया था कि हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से समन्वित जुड़ाव प्रक्रिया की आवश्यकता है और जमीन पर प्रमुख हितधारकों की कमी से बचने के लिए, आगे बढ़ने वाली प्रत्येक परियोजना के लिए सुविचारित मैपिंग की आवश्यकता है।

7. लंबित मामलों के निपटान के संबंध में विशेष अभियान : मंत्रीमंडल सचिवालय के अक्टूबर माह में लंबित मामलों के निपटान के निर्देश के मद्देनजर इस मंत्रालय ने विशेष अभियान के दौरान 802 एमपी संदर्भों का, 125 राज्य सरकार. संदर्भों, 1333 लोक शिकायत एवं 621 पीजी अपीलें का निपटान किया है। इसके अलावा, एमओआरटीएच और एनएचएआई/एनएचआईसीएल सहित उसके संलग्न कार्यालयों की 50,500 फाइलों की समीक्षा की गई है और इस अवधि के दौरान रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार 25,000 से अधिक फाइलों को हटा दिया गया है। मंत्रालय और इसके संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों ने अभियान के एक भाग के रूप में कार्यालय परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया है।
8. स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें: स्थायी वित्त समिति द्वारा अक्टूबर, 2021 माह में कुल 13 परियोजनाओं पर विचार किया गया। स्थायी वित्त समिति द्वारा 301.084 किलोमीटर लंबाई वाली और कुल 6,282.82 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत की 13 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया और अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई।
